Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-16, अंक-21 01-15 नवंबर, 2021 (पाक्षिक) ₹20

भाजपा शासन में मणिपुर 'गेटवे ऑफ डेवलपमेंट' बना है

भारत में टीकाकरण 100 करोड़ के पार

कठिन लक्ष्य असाधारण उपलब्धि

टीम इंडिया की शानदार सफलता

रक्षा निर्माण को मिली नई उड़ान

'पीएम गतिशक्ति योजना' का शुभारंभ

नई दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

इम्फाल (मणिपुर) में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल (डब्ल्यूबीपीएमपी) का शुभारंभ करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

गोवा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भारत ने रच दिया इतिहास

भारत ने 21 अक्टूबर, 2021 को इतिहास रच दिया, जब इसने कोविड-19 रोधी टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराकें लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में टीकाकरण की यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में लगे टीकों की...

14 भाजपा शासन में मणिपुर 'गेटवे ऑफ डेवलपमेंट' बना है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 अक्टूबर, 2021 को उटलो...

16 गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी भाजपा: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर, 2021 को कहा कि भाजपा गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में...

17 'अपना पूरा जीवन मां भारती को हर दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लें'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह प्रवास के दौरान 16 अक्टूबर, 2021 को पोर्ट...

26 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के साथ अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है: नरेन्द्र मोदी

गत 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए...

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 21

श्रद्धांजलि

अजातशत्रु कैलाशपति मिश्र 23

लेख

टीम इंडिया की शानदार सफलता / **नरेन्द्र मोदी** 12

रक्षा निर्माण को मिली नई उड़ान / **राजनाथ सिंह** 24

आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करेगा सहकार मंत्रालय / **विकास आनन्द** 32

अन्य

राष्ट्र को समर्पित हुईं नई सात रक्षा कंपनियां 18

फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को कैबिनेट ने दी मंजूरी 19

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन-अमृत 2.0 को मिली मंजूरी 20

कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा के प्रति पुष्पांजलि है: नरेन्द्र मोदी 28

'मानवाधिकारों की अवधारणा का गरीबों की गरिमा से गहरा संबंध है' 29

आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है, उतनी पहले कभी नहीं रही: नरेन्द्र मोदी 30

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

जब कानून का राज होता है, अपराधियों में डर होता है, तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित और वंचित तक पहुंचता है। यही उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है।

जगत प्रकाश नड्डा

प्रभु श्रीराम हम सभी के आराध्य हैं। महर्षि वाल्मीकिजी ने महाकाव्य रामायण की रचना से प्रभु के सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुंचाकर मानव कल्याण हेतु हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकिजी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।

अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने देश की कई सारी समस्याओं को उनके पारम्परिक स्वरूप से अलग करके देखा व उनका स्थायी समाधान भी किया। मोदीजी ने कृषि, आर्थिक, रक्षा व आंतरिक सुरक्षा, हर क्षेत्र में और सामाजिक न्याय व गरीबी उन्मूलन की दिशा में अभूतपूर्व रिफॉर्म किए हैं।

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई बुलंदी देने की एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति और प्रबल शक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्रीजी को बहुत धन्यवाद!

बी.एल. संतोष

उन्होंने खुद को किसान कहने का हर नैतिक अधिकार खो दिया। समय आ गया है कि अगर उनमें कोई समझदार लोग हैं तो वह राष्ट्र से माफी मांगें और बिना शर्त सरकार से बातचीत करें।

नितिन गडकरी

विजयादशमी के पावन अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्य को पूरा कर रही इन 7 रक्षा कंपनियों में से एक, नागपुर स्थित 'यंत्र इंडिया लिमिटेड' के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। हम डिफेंस के क्षेत्र में नए-नए इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

संपादकीय

100 करोड़ टीकाकरण–एक गौरवशाली क्षण

भारत ने कोविड-19 टीकाकरण का एक सौ करोड़ के आंकड़े का कठिन लक्ष्य पार कर लिया है। इस अद्भुत उपलब्धि से हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। पूरा राष्ट्र इस ऐतिहासिक उपलब्धि से गौरव का अनुभव कर रहा है। गौरव की अनुभूति तब और भी कई गुणा बढ़ जाती है, जब यह ध्यान आता है कि इस मील के पत्थर को देश ने 'मेड इन इंडिया' टीकों एवं स्वयं की क्षमता के आधार पर प्राप्त की है। यह चमत्कृत करने वाली उपलब्धि विश्व मंच पर एक 'आत्मनिर्भर भारत' के आगमन का उद्घोष है जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि एवं करिश्माई नेतृत्व में हर चुनौती को अवसर में बदलने को कृतसंकल्पित है। आज जबकि अनेक विकसित देश भी टीकाकरण को पूरा करने में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भारत ने यह कीर्तिमान मात्र नौ महीने में प्राप्त कर लिया। यह उपलब्धि मोदी सरकार के 'स्पीड, स्केल एवं स्किल' के मंत्र के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है जिससे प्रेरित होकर देश के दुर्गम स्थानों तक में भौगोलिक-सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अर्जित किया गया है।

भारत की सौ करोड़ टीकाकरण की यात्रा अनेक गौरवशाली उपलब्धियों से सुसज्जित है। यह सतत प्रयास की गाथा है जिसमें हर दिन कोई नई सफलता एवं नई गति का गीत समाहित है। जहां 10 करोड़ टीकों के लिए लगने वाले समय को 85 से 11 दिन तक अथक प्रयासों द्वारा प्राप्त किया गया, वहीं भारत ने कई बार एक दिन में एक करोड़ से अधिक टीकाकरण का कीर्तिमान भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर, 2021 को उन्हें 2.5 करोड़ से अधिक टीकों का उपहार देकर देशवासियों ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज जबकि देश में कई राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने शत-प्रतिशत जनसंख्या की कम से कम एक टीका लगाने में सफलता प्राप्त की है, वहीं कुछ अन्य प्रदेशों की उपलब्धियां विश्व के कई अग्रणी देशों से भी अधिक है। लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के टीकाकरण करने जैसा भारी-भरकम कार्य, अब जबकि 31 प्रतिशत जनसंख्या का पूर्ण टीकाकरण एवं 75 प्रतिशत से अधिक को एक टीका लग चुका है, संभव प्रतीत हो रहा है।

भारत ने पूर्व में भी कई बार अपने गौरवशाली उपलब्धियों से अपने आलोचकों को शब्दहीन किया है और इस बार तो वे पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। यह कोई नहीं भूल सकता है कि महामारी के भयंकर दौर में कांग्रेस एवं इसके साथी तथा 'एक्सपर्ट' का जामा ओढ़े इनके सहयोगियों ने देश की महामारी से लड़ने की क्षमता पर कई तरह के आधारहीन प्रश्न खड़े किए थे। यहां तक कि भारत में बने टीकों की गुणवत्ता तक पर संदेह पैदा कर देश में भ्रम की स्थिति बनाने के कुप्रयास किए गए। कांग्रेस के ये प्रायोजित 'एक्सपर्ट' ने इधर-उधर के आंकड़ों को जमाकर देश की असफलता की भविष्यवाणी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही लोग हैं जिनका मानना था कि देश पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क एवं दवाइयां तक नहीं बना पाएगा। परंतु देश की एकजुट शक्ति ने न केवल 'मेड-इन-इंडिया' टीकों से पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया, बल्कि दूसरे देशों को भी उनके संकट के समय में टीके, दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरण, ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराईं। कांग्रेस एवं इसके साथियों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं दृढ़निश्चयी नेतृत्व में आत्मविश्वास से भरे एक 'नए भारत' का उदय हो चुका है जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है।

जिस गति से विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, इससे अब कोई संदेह नहीं कि जल्द ही पूरे देश में टीकाकरण कार्य पूर्ण हो जाएगा

जिस गति से विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, इससे अब कोई संदेह नहीं कि जल्द ही पूरे देश में टीकाकरण कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक ओर जहां निःशुल्क टीके इस विशाल कार्यक्रम का अनूठा अंग है, वहीं दूसरी ओर देश की एकजुटता ने हर चुनौती का दृढ़ता से सामना करने की ऊर्जा दी है। देश के चिकित्सक, नर्स, लैब तकनिशियन, चिकित्सा कर्मचारी, फार्मा सेक्टर, प्रशासनिक वर्ग एवं कोरोना योद्धाओं के सेवा एवं समर्पण से हर भारतीय गौरवान्वित हुआ है और भारत विश्व में एक अद्भुत देश के रूप में उभरा है। आज जबकि भारत अन्य देशों को पुनः टीके उपलब्ध करा रहा है, वहीं 100 करोड़ टीकाकरण के कीर्तिमान एवं इसकी एकजुट शक्ति की चमक से विश्व का परिचय हो रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

भारत ने रच दिया इतिहास

कोविड-19 रोधी टीकों की लगीं 100 करोड़ से अधिक खुराकें

भारत ने 21 अक्टूबर, 2021 को इतिहास रच दिया, जब इसने कोविड-19 रोधी टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराकें लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में टीकाकरण की यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में लगे टीकों की संख्या से दोगुनी, जापान से पांच गुना, जर्मनी से नौ गुना और फ्रांस से 10 गुना अधिक है

कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी, 2021 को हुई थी और इसके पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए थे। इसके बाद दो फरवरी से अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण आरंभ हुआ था। टीकाकरण मुहिम का अगला चरण एक मार्च से आरंभ हुआ, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के सभी लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाने शुरू किए गए।

देश में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण एक अप्रैल से आरंभ हुआ था और 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण एक मई से शुरू हुआ।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में टीकाकरण मुहिम शुरू होने के 85 दिन बाद तक 10 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी थीं, इसके 45 और दिन बाद भारत ने 20 करोड़ का आंकड़ा छुआ और उसके 29 दिन बाद यह संख्या 30 करोड़ पहुंच गई। देश को 30 करोड़ से 40 करोड़ तक पहुंचने में 24 दिन लगे और इसके 20 और दिन बाद छह अगस्त को देश में टीकों की दी गई खुराकों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ पहुंच गई। इसके बाद उसे 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 76 दिन लगे।

देश में टीकाकरण के पात्र वयस्कों में से करीब 75 प्रतिशत लोगों को कम से कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि करीब 31 प्रतिशत लोगों को टीके की दोनों खुराक लग चुकी हैं

उल्लेखनीय है कि देश में टीकाकरण के पात्र वयस्कों में से करीब 75 प्रतिशत लोगों को कम से कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि करीब 31 प्रतिशत लोगों को टीके की दोनों खुराक लग चुकी हैं।

सच तो यह है कि 100 करोड़ से अधिक

टीकाकरण करना आसान काम नहीं था। देश के दूरदराज इलाकों में कोविड टीका पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए विशेष अभियान चलाए गए और ड्रोन से भी टीके की आपूर्ति की गई। साथ ही, स्थानीय स्तर पर युवाओं को तैयार किया गया और आशा कार्यकर्ता व कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं की भी मदद ली गई। गौरतलब है कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने उच्च स्तर पर एक निगरानी तंत्र विकसित किया है। प्रतिदिन के आधार पर पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है और जरूरत के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

100 करोड़ टीकाकरण पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश को बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि देश ने आज एक इतिहास रचा है। सभी देशवासियों ने मिलकर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पार कर लिया है। विश्व पटल पर भारत ने आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।

130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की विजयः नरेन्द्र मोदी

100 करोड़ से अधिक खुराक लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने के लिए काम किया है।

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने इतिहास रचा। हम 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, उद्यम और उनकी सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण को पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार।

श्री मोदी देश के यह उपलब्धि हासिल करने के मौके पर नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे। उन्होंने वहां अस्पताल के अधिकारियों, कर्मियों और कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया भी उनके साथ मौजूद थे।

श्री मांडविया ने एक ट्वीट करके देश को यह उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी और कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने लिखा कि बधाई हो भारत! यह दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समर्थ नेतृत्व का प्रतिफल है।

इस असाधारण उपलब्धि पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने जिस रफ्तार से 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ है ये दर्शाता है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पित है। इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं व सभी स्वास्थ्यकर्मियों और जनता को बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि कठिन संघर्ष के समय में अद्भुत सामर्थ्य का परिचय देते हुए भारत ने 10 माह से कम समय में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि होने के साथ ही विश्व पटल पर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने इस उपलब्धि के लिए देश को बधाई देते हुए कहा कि यह मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत को एक और मील का पत्थर स्थापित करने– कोविड-19 की एक अरब खुराक देने– के लिए बहुत-बहुत बधाई। मजबूत नेतृत्व, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, स्वास्थ्य एवं अग्रिम मोर्चे के संपूर्ण कार्यबल के और खुद लोगों के समर्पित प्रयासों के बिना इतने कम समय में यह असाधारण उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) भारत ने भी यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सरकार को बधाई दी और टीकाकरण की गति

प्रधानमंत्री मोदीजी की प्रेरणा से भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान रचा है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन किया और हेल्थ एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री नड्डा ने 21 अक्टूबर, 2021 को कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण काल में जब एक अंधकार का युग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनने लगा था, तब ऐसी विषम और विकट परिस्थितियों में महानायक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 130 करोड़ भारतवासियों को उम्मीद की रोशनी दी। उन्होंने विश्वास की किरणों से देशवासियों को न सिर्फ जीत में यकीन कराया, बल्कि कोविड के विरुद्ध अभेद्य किले का निर्माण कर समस्त देशवासियों को सुरक्षित भी किया और देश के अर्थचक्र की गति को भी रुकने नहीं दिया।

महानायक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 130 करोड़ भारतवासियों को उम्मीद की रोशनी दी

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड को परास्त करने के लिए Pro-Active और pre-emptive measures लेते हुए 14 अप्रैल, 2020 को ही 'वैक्सीन टास्क फ़ोर्स' गठित कर दिया था। 8 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्रीजी ने कोविड वैक्सीन निर्माण की तीनों फैसिलिटी सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जायडस बायोटेक का दौरा किया और वैक्सीन निर्माण का जायजा लिया। टास्क फ़ोर्स के गठित होने के 9 महीने के भीतर ही भारत ने न केवल दो-दो विश्वस्तरीय मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन का निर्माण किया, बल्कि 278 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि भारत में 'ये नहीं हो सकता' से 'हम यह कर सकते हैं' और 'ये होकर रहेगा' का सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने देशवासियों को यह अहसास दिलाया है कि अगर 130 करोड़ देशवासी ठान लें तो भारत कदम-कदम पर सफलता के नए अध्याय जोड़ सकता है और देश को हर मुश्किल से निजात दिलाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीजी को, पूरे देश को, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा था कि तय समय में वैक्सीन बन जायेगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं था और वे लगातार इस प्रक्रिया को हतोत्साहित करने में लगे रहे, लेकिन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए हमने यह मुकाम हासिल किया है। 16 जनवरी, 2021 से भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इसके बाद 19 फरवरी को एक करोड़, 11 अप्रैल को 10 करोड़, 12 जून को 25 करोड़, 6 अगस्त को 50 करोड़, 13 सितंबर को 75 करोड़ और आज 21 अक्टूबर को भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा और हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के अथक परिश्रम से भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान रचा है।

श्री नड्डा ने कहा कि पूरे यूरोपीय संघ में अब तक जितने कोविड वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किये गए हैं, उससे भी कहीं अधिक टीके भारत ने लगाए हैं। अमेरिका में हुए कुल वैक्सीनेशन से लगभग ढाई गुना अधिक वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के कम एक खुराक के साथ 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत कम से कम पांच बार एक दिन में एक करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है जो अपने-आप में एक रिकॉर्ड है। 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर समग्र राष्ट्र ने वैक्सीनेशन के यज्ञ रूपी 'जन अभियान' में अपनी समग्र भागीदारी देते हुए एक दिन में ढाई करोड़ से अधिक नागरिकों का टीकाकरण करके देश को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में मदद की।

उन्होंने कहा कि यह समय फिर से हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की सफलता की सराहना करने का है, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में टीके विकसित किए। यह समय फिर से हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साहस और समर्पण का सम्मान करने का है, जिन्होंने इतनी कम अवधि में 100 करोड़ टीकाकरण के मील का पत्थर पार करने में हमारी मदद की। ■

“ ऐतिहासिक व गौरवमयी क्षण! आज भारत ने 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व व निरंतर प्रोत्साहन से एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है जिसने पूरे विश्व को नए भारत की अपार क्षमताओं से पुनः परिचित कराया है।

अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

“ कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई मे आज भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कम समय में 100 करोड़ वैक्सिनेशन डोज़ देने के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया है।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

“ न्यू इंडिया का नया रिकॉर्ड!! प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने आज 100 करोड़ टीकाकरण पूर्ण करके विश्व के इतिहास में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह हमारे स्वास्थ्यकर्मियों की निःस्वार्थ सेवा और समर्पण के कारण संभव हुआ है।

नितिन गडकरी, केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री

“ बधाई हो भारत! हमने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण करने का एक ऐतिहासिक मुकाम प्राप्त किया है। हमारे कोविड योद्धाओं, हमारे स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को नमन, जिन्होंने दिन-रात काम करके हमें यह हासिल करने में मदद की है।

मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

हालिया महीनों में तेज करने के भारत के प्रयासों का स्वागत किया। यूनिसेफ भारत ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक साल से कम समय में एक अरब खुराक देने में साजो-सामान संबंधी जटिलताओं के मद्देनजर यह उपलब्धि शानदार है।

उसने कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्यकर्मियों को देश के हर हिस्से में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए चौबीसों घंटे काम करते देखा है। कई कर्मियों ने लोगों को टीका लगाने के लिए सबसे दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में यात्रा की। हम इन स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत को सलाम करते हैं। उनके और वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, टीका निर्माताओं, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य प्रबंधकों के समर्पण के बिना हम इस मील के पत्थर को हासिल नहीं कर पाते। ■

ऐतिहासिक कोविड टीकाकरण पर पूरे देश में मना जश्न

भारत द्वारा कोविड-19 के टीके की 100 करोड़ खुराक देने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) देशभर में 100 स्मारकों को तिरंगे के रंग में रोशन किया।

तिरंगे के रंगों में रोशन किए गए 100 स्मारकों में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल- दिल्ली में लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुबमीनार, उत्तर प्रदेश में आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ओडिशा में कोणार्क मंदिर, तमिलनाडु में ममल्लापुरम रथ मंदिर, गोवा में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च, मध्य प्रदेश में खजुराहो, राजस्थान में चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के किले, बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष और गुजरात में धोलावीरा (हाल ही में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया) शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के लाल किला से एक गाना और एक ऑडियो-वीडियो फिल्म लॉन्च किया। रेलवे स्टेशनों पर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को यह उपलब्धि बताई गयी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सार्वजनिक घोषणा के ज़रिए टीकाकरण के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर लोगों को सूचना दी।

स्पाइस जेट ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने विमान को विशेष तौर पर सजाया, जिस पर स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी तस्वीर है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। ■

दुनिया भर के नेताओं ने भारत को दी बधाई

दुनिया भर के नेताओं ने भारत को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने पर बधाई दी और इसे एक बड़ी व असाधारण उपलब्धि बताया। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत द्वारा 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पार करने पर विश्व नेताओं द्वारा दी गयी शुभकामनाओं के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को एक अरब से अधिक कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए बधाई दी। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में तीन-चौथाई वयस्कों को पहली डोज दी जा चुकी है और लगभग 30 प्रतिशत को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। कोविड-19 से बड़ी आबादी की रक्षा करने और वैक्सीन इक्विटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के आपके प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को बधाई।

–टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ

न केवल आपके देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है भारत ने कोविड-19 टीकाकरण खुराक के एक बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। मैं भूटान के लोगों की ओर से भारत को बधाई देता हूं! @narendramodi @PMOIndia

–लोटे शेरिंग, प्रधानमंत्री, भूटान

इस विशाल कार्य को पूर्ण करने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी, चिकित्सा समुदाय और भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई। सुरक्षित रहने के दौरान आगे बढ़ना और नए सामान्य के साथ तालमेल बिठाने का तरीका एक सफल टीकाकरण अभियान पर अत्यधिक निर्भर है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बधाई।

–महिंदा राजपक्षे, प्रधानमंत्री, श्रीलंका

भारत को बधाई, जिसने अब तक 1 बिलियन कोविड-19 टीके लगाए हैं। वैक्सीन की पहुंच बेहतर और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

–डॉ. लाजर चकवेरा, राष्ट्रपति, मलावी

भारत को 1 बिलियन कोविड-19 टीकाकरण के लिए बधाई – यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है!

–टांडी दोरजी, विदेश मंत्री, भूटान

भारत के सफल कोविड-19 टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई, जिसके दौरान अब तक भारतीय लोगों को 1 बिलियन से अधिक टीके लगाए गए हैं। ये जीवन रक्षक टीके वैश्विक महामारी को हराने में हम सभी की मदद कर रहे हैं।

–नफ्ताली बेनेट, प्रधानमंत्री, इज़राइल

पीएम नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार को कोविड-19 टीकों की 1 बिलियन खुराक देने के लिए बधाई, जो भारतीय लोगों के नवाचार और एकजुटता को प्रदर्शित करता है। मालदीव का कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और टीकाकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत को भी धन्यवाद।

–इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, राष्ट्रपति, मालदीव

हम भारत को कोविड-19 वैक्सीन की एक अरब खुराक देने की असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। मैं कोविड-19 से लड़ने में भारत की सफलताओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र एवं उससे आगे महामारी को समाप्त करने में मदद करने के प्रयासों के लिए सराहना करता हूं।

–एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री, अमेरिका

भारत को कोविड-19 वैक्सीन की अपनी 1 अरबवीं खुराक देने के लिए बधाई! हम दुनिया भर में निर्यात और उपयोग के लिए वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। क्वाड के साथ अमेरिका और भारत दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रम और महामारी को समाप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

–वेंडी आर. शर्मन, उप विदेश मंत्री, अमेरिका

भारत ने वैक्सीन की 1 बिलियन खुराकें दी हैं, जो भारत के नवाचार, बड़े पैमाने पर निर्माण करने की क्षमता और कोविन द्वारा समर्थित लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मनसुख मांडविया को बधाई।

–बिल गेट्स

100 करोड़ टीकाकरण देश की शक्ति का प्रतिबिंब है: नरेन्द्र मोदी

यदि बीमारी कोई भेदभाव नहीं करती है, तो टीकाकरण में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि पात्रता को लेकर वीआईपी संस्कृति, टीकाकरण अभियान पर हावी न हो सके

गत 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन खुराक की कठिन लेकिन उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि 130 करोड़ देशवासियों के समर्पण का परिणाम है और यह सफलता भारत की सफलता है तथा प्रत्येक देशवासी की सफलता है।

श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि देश की शक्ति का प्रतिबिंब है, यह इतिहास के एक नए अध्याय का निर्माण है। यह 'न्यू इंडिया' की एक तस्वीर है। 'न्यू इंडिया', जो कठिन लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करना भी जानता है।

उन्होंने कहा कि आज कई लोग भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की तुलना दुनिया के अन्य देशों से कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने जिस गति से 100 करोड़, 1 अरब के आंकड़े को पार किया है, उसकी भी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इस किस्म के विश्लेषण में हालांकि भारत द्वारा की गई शुरुआत की बात को अक्सर छोड़ दिया जाता है।

श्री मोदी ने कहा कि विकसित देशों के पास टीकों के शोध एवं विकास के मामले में दशकों की विशेषज्ञता थी। भारत ज्यादातर इन देशों द्वारा बनाए गए टीकों पर निर्भर रहता था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, तो इस वैश्विक महामारी से लड़ने की भारत की क्षमता को लेकर कई सवाल उठाए गए। टीके की 100 करोड़ खुराक की यह उपलब्धि हासिल कर कई सवालों जैसे कि दूसरे देशों से इतने टीके खरीदने के लिए भारत को पैसा कहां से मिलेगा? भारत को टीका कब मिलेगा? भारत के लोगों को टीका मिलेगा भी या नहीं? क्या भारत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों का टीकाकरण कर पाएगा? का जवाब दिया गया।

भारत ने अपने नागरिकों को न सिर्फ टीके की 100 करोड़ खुराकें दी हैं, बल्कि यह काम निःशुल्क भी किया है। भारत को दुनिया में फार्मा हब के रूप में जो स्वीकृति मिली है, उसे और मजबूत किया जाएगा

निःशुल्क किया गया टीकाकरण का काम

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को न सिर्फ टीके की 100 करोड़ खुराकें दी हैं, बल्कि यह काम निःशुल्क भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में फार्मा हब के रूप में जो स्वीकृति मिली है, उसे और मजबूत किया जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस किस्म के सवाल भी उठाए गए कि क्या इतना संयम और अनुशासन यहां संभव होगा? उन्होंने कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र का अर्थ है, सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ। इस देश ने 'मुफ्त टीका और सबके लिए टीका' अभियान की शुरुआत की। गरीब-अमीर, ग्रामीण-शहरी लोगों को समान रूप से टीके की खुराकें दी गईं।

उन्होंने कहा कि इस देश का एक ही मंत्र है कि अगर रोग कोई भेदभाव नहीं करता, तो टीकाकरण में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से यह सुनिश्चित किया गया कि टीकाकरण अभियान में कोई वीआईपी संस्कृति हावी न हो।

श्री मोदी ने कहा कि इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए थे कि भारत में ज्यादातर लोग टीका लेने के लिए टीकाकरण केंद्र नहीं जायेंगे। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी टीके को लेकर होने वाली हिचकिचाहट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन भारत की जनता ने टीके की 100 करोड़ खुराकें लेकर इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक अभियान 'सबका प्रयास' होता है और अगर सभी के प्रयासों को समन्वित किया जाए, तो परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इस महामारी के खिलाफ देश

शेष पृष्ठ 13 पर...

टीम इंडिया की शानदार सफलता

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

भारत ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र नौ महीने बाद ही 21 अक्तूबर, 2021 को टीके की 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोविड-19 से मुकाबला करने में यह यात्रा अद्भुत रही है, विशेषकर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थीं। मानवता 100 साल बाद इस तरह की वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी और किसी को भी इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमें यह स्मरण होता है कि उस समय स्थिति कितनी अप्रत्याशित थी, क्योंकि हम एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, जो तेजी से अपना रूप भी बदल रहा था।

चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। इसे वास्तव में एक भगीरथ प्रयास मानना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए हैं। पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए, मान लें कि प्रत्येक टीकाकरण में एक स्वास्थ्यकर्मी को केवल दो मिनट का समय लगता है।

इस दर से, इस उपलब्धि को हासिल करने में लगभग 41 लाख मानव दिवस या लगभग 11 हजार मानव वर्ष लगे। गति और पैमाने को प्राप्त करने तथा इसे बनाए रखने के किसी भी प्रयास के लिए सभी हितधारकों का विश्वास महत्वपूर्ण है। इस अभियान की सफलता के कारणों में से एक, वैक्सीन तथा बाद की प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा था, जो अविश्वास और भय पैदा करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद कायम रहा।

हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जो दैनिक जरूरतों के लिए भी विदेशी ब्रांडों पर भरोसा करते हैं। हालांकि, जब कोविड-19 वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण बात सामने आई,

चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। इसे वास्तव में एक भगीरथ प्रयास मानना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए हैं

तो देशवासियों ने सर्वसम्मति से 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन पर भरोसा किया। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक बदलाव है। यह टीका अभियान इसका उदाहरण है कि यहां के नागरिक और सरकार जनभागीदारी की भावना से लैस होकर साझा लक्ष्य के लिए साथ आएं, तो यह देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है।

जब भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। पर जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की तरह लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए, तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। हमारे युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को इसका श्रेय जाता है कि टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों की तुलना में कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा है।

आज तक केवल कुछ चुनिंदा देशों ने ही अपने स्वयं के टीके विकसित किए हैं। 180 से भी अधिक देश टीकों के लिए जिन उत्पादकों पर निर्भर हैं, वे बेहद सीमित संख्या में हैं। यही नहीं, जहां एक ओर भारत ने 100 करोड़ खुराक का अविश्वसनीय या जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों देश अब भी अपने यहां टीकों की आपूर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं! इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत ही भारत टीकों के मामले में 'आत्मनिर्भर' बन गया है।

भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में सिर्फ उत्पादन करना ही काफी नहीं है। इसके

लिए अंतिम व्यक्ति तक को टीका लगाने और निर्बाध लॉजिस्टिक्स पर भी फोकस होना चाहिए। इसमें निहित चुनौतियों को समझने के लिए जरा इसकी कल्पना करें कि टीके की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया जाता है। पुणे या हैदराबाद स्थित किसी दवा संयंत्र से निकली शीशी को किसी भी राज्य के हब में भेजा जाता है, जहां से इसे जिला हब तक पहुंचाया जाता है।

फिर वहां से इसे टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाता है। इसमें विमानों की उड़ानों और ट्रेनों के जरिये हजारों यात्राएं सुनिश्चित करनी पड़ती हैं। टीकों को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरी यात्रा के दौरान तापमान को एक खास रेंज में बनाए रखना होता है, जिसकी निगरानी केंद्रीय रूप से की जाती है। इसके लिए एक लाख से भी अधिक शीत-शृंखला (कोल्ड-चेन) उपकरणों का उपयोग किया गया। राज्यों को टीकों के वितरण कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दी गई थी, ताकि वे अपने अभियान की बेहतर योजना बना सकें और टीके पूर्व-निर्धारित तिथि को ही उन तक सफलतापूर्वक पहुंच सकें। अतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व प्रयास रहा है।

इन सभी प्रयासों को कोविन के एक मजबूत तकनीकी मंच से जबर्दस्त मदद मिली। इसने यह सुनिश्चित किया कि टीकाकरण अभियान न्यायसंगत, मापनीय, ट्रैक करने योग्य और पारदर्शी बना रहे। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि एक गरीब मजदूर अपने गांव में पहली खुराक ले सकता है और उसी टीके की दूसरी खुराक तय समय अंतराल पर उस शहर में ले सकता है, जहां वह काम करता है।

2015 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मैंने कहा था कि हमारा देश 'टीम इंडिया' की वजह से आगे बढ़ रहा है और यह 130 करोड़ लोगों की एक बड़ी टीम है। जनभागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी से देश चलाएंगे, तो देश हर पल 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। हमारे टीकाकरण अभियान ने फिर इस 'टीम इंडिया' की ताकत दिखाई है।

टीकाकरण अभियान में भारत की सफलता ने दुनिया को दिखाया है कि 'लोकतंत्र हर उपलब्धि हासिल कर सकता है।' मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मिली सफलता हमारे युवाओं, शोधकर्ताओं और सरकार के सभी स्तरों को सार्वजनिक सेवा वितरण के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी, जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मॉडल होगा। ■

पृष्ठ 11 का शेष...

की लड़ाई में जन-भागीदारी को रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में रखा।

पूरा टीकाकरण कार्यक्रम विज्ञान पर आधारित है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत का पूरा टीकाकरण कार्यक्रम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारो दिशाओं में पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिये गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीन कार्यक्रम विज्ञान से पैदा हुआ, विज्ञान से आगे बढ़ा और वह विज्ञान पर आधारित है।

श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन के बनने से पहले और वैक्सीन लगाने तक का पूरा अभियान वैज्ञानिक समझ पर आधारित था। उत्पादन को बढ़ाने की चुनौती भी थी। इसके बाद विभिन्न राज्यों और दूर-दराज के इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने की चुनौती थी। लेकिन वैज्ञानिक तरीके और नये प्रयोगों से देश ने इन चुनौतियों का समाधान निकाल लिया। संसाधनों को असाधारण तेजी से बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि भारत में बने कोविन प्लेटफार्म से न केवल आम जन को सुविधा मिली, बल्कि हमारे मेडिकल स्टाफ के काम में भी आसानी पैदा हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और विदेश के विशेषज्ञ और कई एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत सकारात्मक हैं। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप में रिकॉर्ड निवेश के साथ ही यूनिकॉर्न बन रहे हैं। आवासीय सेक्टर में भी नई ऊर्जा देखी जा रही है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई सुधार और पहलें की गई हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने में बड़ी भूमिका निभायेंगी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कृषि सेक्टर ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाये रखा। आज खाद्यान्न की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है। धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रही है।

श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे हर छोटी से छोटी चीज जो भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिये। उन्होंने कहा कि यह सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन-आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल होना, यह हमें व्यवहार में उतारना होगा।

उन्होंने कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना जानता है, लेकिन इसके लिये हमें निरंतर सावधान रहने की जरूरत है। श्री मोदी ने जोर देते हुये कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी; जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। उन्होंने कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाया जाये। ■

भाजपा शासन में मणिपुर 'गेटवे ऑफ डेवलपमेंट' बना है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 अक्टूबर, 2021 को उटलो, नामबोल (मणिपुर) के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मणिपुर में डबल इंजन की सरकार द्वारा किये गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य की जनता से पुनः भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। जनसभा में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी, मणिपुर के महाराजा लीशेम्बा सनजाओबा, केंद्रीय मंत्री श्री आर. के. रंजन सिंह, केन्द्रीय मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, मणिपुर के भाजपा प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा, श्री अजय जामवाल एवं श्री अशोक सिंघल सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री नड्डा जनसभा को संबोधित करने से पहले उटलो गांव में ही भाजपा के एक बूथ अध्यक्ष के घर गए, उनसे एवं उनके परिजनों से मुलाक़ात की और उन्हीं के घर दोपहर का भोजन किया।

श्री नड्डा ने कहा कि उजाले की अहमियत तभी होती है जब आपने अंधकार से संघर्ष किया हुआ होता है। कांग्रेस की सरकार में मणिपुर में आये दिन कर्फ्यू, हड़ताल और अराजकता की स्थिति बनी रहती थी। विकास ठप्प पड़ा था, लोगों को जरूरतों की चीजें भी मयस्सर नहीं थी। कांग्रेस सरकार के मंत्री और नेता हाथ पर हाथ धरे केवल और केवल राजनीति को हवा देने में लगे रहते थे और समाज को बांटकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते थे। मणिपुर में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में विकास को नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर ने अंधेरे से उजाले और भ्रष्टाचार से विकास तक की यात्रा तय की है। कांग्रेस की सरकार में मणिपुर की सड़कों पर जनता का खून बहता था, आज तारकोल बिछकर नई सड़कें बन रही हैं, नए पुल बन रहे हैं और रेलमार्ग का निर्माण हो रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं से मणिपुर की जनता का जीवन स्तर ऊपर उठा है। उज्ज्वला योजना के तहत मणिपुर में 1.56 लाख गैस कनेक्शन दिए गए, सौभाग्य योजना से राज्य के लगभग एक लाख घरों में बिजली पहुंची और उजाला योजना के तहत प्रदेश में तीन लाख एलईडी बल्ब का वितरण हुआ जिससे लगभग 16 करोड़ रुपये के बिजली बिल की बचत हुई। कोरोना के समय गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत मणिपुर की लगभग 10 लाख महिलाओं के एकाउंट में केंद्र सरकार की ओर पांच-पांच सौ रुपये की तीन किस्तें, अर्थात् 1,500 रुपये दिए गए। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत मणिपुर के लगभग 11,000 नागरिक लाभ उठा चुके हैं जिस पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत मणिपुर के लगभग

तीन लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर में विकास की नई क्रांति की शुरुआत हुई है। इनर लाइन परमिट से कल्चरल हेरिटेज के साथ-साथ परिसंपत्तियों को भी सुरक्षित किया जा रहा है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कार्य योजना बनी है और गो टू हिल्स जैसे कार्यक्रमों का सूत्रपात हुआ है। इनोवेटिव मणिपुर के तहत कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है। लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की लागत से 16 हाइवे पर काम चल रहा है। जल-जीवन मिशन पर राज्य में लगभग 906 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। असम से मणिपुर को रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। जिरीबाम-इंफाल नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है जो 2023 तक पूरा हो जाएगा। ये केवल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि विकास का रोडमैप है। हमारी सरकार में मणिपुर में अब तक 300 परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है और 30 अन्य परियोजनाओं का श्रीगणेश किया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से 7 वीमेंस मार्किट शुरू किये गए हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन शुरू किया गया है। साथ ही, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देते हुए मणिपुर में 9.06 मेगावाट का एक प्लांट भी लगाया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज मणिपुर स्पोर्ट्स का एक नया डेस्टिनेशन बन चुका है। प्रधानमंत्रीजी के 'खेलो इंडिया' अभियान से मणिपुर को और लाभ उठाना चाहिए। चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक्स - हर जगह मणिपुर के खिलाड़ी अव्वल हैं। मुक्केबाजी से लेकर एथलेटिक्स में मणिपुर के खिलाड़ियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और मल्टीस्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है।

केंद्रीय योजनाओं से मणिपुर की जनता का जीवन स्तर ऊपर उठा है। उज्ज्वला योजना के तहत मणिपुर में 1.56 लाख गैस कनेक्शन दिए गए, सौभाग्य योजना से राज्य के लगभग एक लाख घरों में बिजली पहुंची

डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर नई उम्मीद के साथ विकास के पथ पर तेज गति से बढ़ चला है। पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास को अनदेखा किया जाता था लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में मणिपुर 'गेटवे ऑफ डेवलपमेंट' बना है।

प्रबुद्धजनों से संवाद

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 अक्टूबर 2021 को अपने मणिपुर प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन सिटी कन्वेंशन सेंटर इंफाल में शिक्षा, खेल, विज्ञान सहित अलग-अलग क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराने वाले विजेताओं, समाज की प्रमुख हस्तियों एवं प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया और उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चल रही विकास यात्रा से परिचित कराया। इस कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ओलम्पियन मैरी कॉम और मणिपुर के भाजपा प्रभारी डॉ. संबित पात्रा सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि कोविड के संक्रमण काल के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह उनके आह्वान को एक साथ मिलकर सफल बनाया और देश को कोरोना के प्रकोप से उबरने में अपना योगदान दिया, इसने देश में सहभागिता से समस्याओं के समाधान की दिशा में एक नया अध्याय लिखा है। कोरोना काल में जन-जन की भलाई के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक योजनाओं की शुरुआत की, ताकि गरीब जनता को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गरीब कल्याण योजना के तहत 9 महीनों तक मार्च से लेकर नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज का प्रबंध किया गया। इस वर्ष भी गरीब कल्याण योजना मार्च से लेकर नवंबर तक चलाई जा रही है। यह अपने आप में जनसेवा का एक नया आयाम है। 20 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में कोरोना काल में 500 की तीन किस्तों के रूप में पंद्रह 1,500 की आर्थिक सहायता दी गई। प्रधानमंत्रीजी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना से प्रवासी मजदूरों को अपने ही गृह जिले में रोजगार उपलब्ध कराया। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से देश को चुनौतियों से निपटने की राह मिली।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण की राशि सीधे गरीबों के खाते में जाती है। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्रीजी ने कई योजनाएं शुरू की हैं। किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों को 9 किस्तों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। साथ ही, कृषि अवसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 60 साल से अधिक उम्र के लघु और सीमांत किसानों के लिए 3000 की मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। प्रति बोरी डीएपी पर 1,200 की सब्सिडी दी जा रही है।

नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 अक्टूबर 2021 को इंफाल, मणिपुर में नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और पार्टी कार्यालय को कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का केंद्र बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा मणिपुर को एक विकसित राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। श्री नड्डा ने कहा कि कार्यालय हार्डवेयर और कार्यकर्ता सॉफ्टवेयर होते हैं तथा किसी भी पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कोष और इसे संचालित करने के लिए कार्यालय आवश्यक है। ■

गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी भाजपा: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर, 2021 को कहा कि भाजपा गोवा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के लिए तैयार है। श्री शाह ने तालेगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने प्रवास के दौरान भाजपा विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने दक्षिण गोवा के धारबंदोरा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के 'भूमि पूजन' के एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया।

श्री मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री पर्रिकर को युगों-युगों तक याद रखेगा क्योंकि उनके नेतृत्व में हमारे सशस्त्र बल के जवानों को 'वन रैंक-वन पेंशन' की सौगात मिली थी।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कई वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद एक आम बात थी, लेकिन जब पुंछ में हमला हुआ, तो पहली बार भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई और तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भाजपा जयघोष के बीच श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और गोवा की भाजपा सरकार ने पिछले एक दशक में कई विकास कार्यों को पूर्ण किया है और राज्य को एक स्थिर सरकार दी है। उन्होंने कहा कि गोवा की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार राज्य के विकास में मदद करेंगी।

कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन वह आज ही अपना मन बना लें। भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत से वापस लाओ, मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के विकास कार्यों पर मुहर लगाओ।

गोवा में 100 प्रतिशत कोविड टीकाकरण

श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत की सराहना करते हुए कहा कि गोवा में पात्र आबादी को पहली खुराक देकर शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गोवा में कोविड-19 महामारी से निपटने का तरीका देश में सबसे अच्छा है।

गोवा सरकार ने हर चुनौती का बड़ी कुशलता से मुकाबला किया और कोरोना महामारी का बखूबी सामना किया। इस बीमारी का सामना करते हुए यह देश के अग्रणी राज्यों में से एक था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि मोपा हवाई अड्डा एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का बनाने और राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकास के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

एनएफएसयू परिसर का शिलान्यास

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की आधारशिला रखते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि गोवा में शुरू होने वाले फोरेंसिक विश्वविद्यालय का उद्देश्य दोषसिद्धि दर में सुधार करना, गोवा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति की कमी को पूरा करना है।

उन्होंने कहा कि छह साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक वैज्ञानिकों का दौरा अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, श्री शाह ने कहा कि देश के 600 जिलों में जिला स्तर पर फॉरेंसिक टीमें तैनात होनी चाहिए और मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें 30,000-40,000 फोरेंसिक वैज्ञानिकों की जरूरत होगी। हम उन्हें कहां से लाएंगे? कुशल जनशक्ति की कमी है। केवल शिक्षा ही इसका उत्तर है और इसीलिए फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में रोजगार भी मिलेगा। 10 साल में लोग कहेंगे कि ज्यादातर फॉरेंसिक वैज्ञानिक गोवा से आते हैं। उन्होंने कहा कि गोवा एनएफएसयू को पर्यटन, एनडीपीएस अधिनियम और तटीय पुलिसिंग जैसे गोवा से संबंधित मुद्दों को भी पूरा करना चाहिए।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के गोवा प्रभारी श्री देवेन्द्र फडणवीस, मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

'अपना पूरा जीवन मां भारती को हर दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लें'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह प्रवास के दौरान 16 अक्टूबर, 2021 को पोर्ट ब्लेयर में कार्यकर्ता व बुद्धिजीवी सम्मलेन को संबोधित किया और आह्वान किया कि आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता स्वयं को भारत माता के प्रति पुनर्समर्पित करें और अपना पूरा जीवन मां भारती को हर दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लें।

श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकरजी इसी अंडमान निकोबार की भूमि पर 10 वर्ष बिताये और यहां की सेल्युलर जेल में अपार यातनाएं झेलीं, लेकिन उन्होंने झुकने का नाम नहीं लिया।

श्री शाह ने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए किये जा रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर मोदीजी ने ढेर सारे विकास कार्य किये हैं। जल जीवन मिशन में 66 हजार परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया गया है। 'स्वनिधि योजना' यहां शत-प्रतिशत पहुंची है। हर घर में बिजली पहुंचाई गई है, एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड यहां शत-प्रतिशत लागू हो चुका है। 129 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। केरोसिन मुक्त अंडमान निकोबार के हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है। 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत 11,500 लोगों को 5 लाख रुपये की सुविधा का सारा फायदा पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है।

जल जीवन मिशन में 66 हजार परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया गया है। स्वनिधि योजना यहां शत प्रतिशत पहुंची है। हर घर में बिजली पहुंचाई गई है

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 सालों तक कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस दौरान अंडमान निकोबार के हर घर में शौचालय पहुंचा पाए थे? हर घर में बिजली पहुंचा पाए थे क्या? गरीब व्यक्ति को 'आयुष्मान भारत' जैसी योजना का लाभ पहुंचा पाए थे क्या? केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के 13 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित कराने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तो चेन्नई से अंडमान निकोबार तक सबमरीन केबल बिछाने का विचार क्या कांग्रेस के मन में आई भी थी क्या? प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में यह योजना शुरू की जो 2020 में समाप्त हो गई, आज अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी की सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं।

श्री शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस के समय एक सरकार सोचती थी, दूसरी सरकार योजना बनाती थी, तीसरी सरकार टेंडर निकालती थी, चौथी सरकार काम शुरू करती थी और पांचवीं सरकार आई तो उसका उद्घाटन करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक नई कार्य-संस्कृति बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही किसी परियोजना का भूमिपूजन करते हैं और उसका लोकार्पण भी, यही वजह है कि विकास इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। 1,224 करोड़ रुपये की लागत से अंडमान निकोबार के 12 प्रमुख द्वीपों को जोड़ने की परियोजना समाप्त हो चुकी है। पोर्ट ब्लेयर में 200 जीबीपीएस और यहां के अन्य द्वीपों में 100 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी आज उपलब्ध है। अंडमान निकोबार का फ्लैग पॉइंट, जहां सुभाष बाबू ने आजाद भारत का पहला तिरंगा फहराया और कहा था कि मैं अपने जीवन में आजाद भारत का तिरंगा फहराते देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया, उस जगह को भुला दिया गया था। इस महत्वपूर्ण घटना के 75 वर्ष पूरे होने पर, 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अंडमान निकोबार आए और 100 फिट का ऊंचा तिरंगा फहराकर सुभाष बाबू की स्मृति को पुनर्जीवित करने का काम किया। अंडमान निकोबार के तीन द्वीपों का पुनर्नामकरण किया गया- नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। कांग्रेस को कभी भी इन सब चीजों का विचार नहीं आया। सुभाष बाबू के जन्मदिन को 'पराक्रम दिवस' का नाम देकर देश के बच्चों और युवाओं को सुभाष बाबू बनने की प्रेरणा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कर दिखाया। ■

राष्ट्र को समर्पित हुईं नई सात रक्षा कंपनियां

आने वाले समय में यह नई सात कंपनियां देश की सैन्य ताकत के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करेंगी तथा इन नई कंपनियों के लिए देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं

गत 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

दरअसल, केंद्र सरकार ने कार्यात्मक स्वायत्तता, दक्षता एवं नई विकास क्षमता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से सौ फीसदी सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का फैसला किया। ये 7 नई रक्षा कंपनियां हैं- म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल); आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी); एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया); ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) (ट्रूप कम्फर्ट आइटम्स); यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल); इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)।

अपने संबोधन में श्री मोदी ने आज विजयादशमी के शुभ अवसर और इस दिन हथियार एवं गोला-बारूद की पूजा करने की परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में हम शक्ति को सृजन के माध्यम के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसी भावना से देश ताकत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है।

श्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज ही पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। उन्होंने कहा कि कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, यह हम सभी के लिए प्रेरणा है।

श्री मोदी ने कहा कि आयुध कारखानों के पुनर्गठन और सात नई कंपनियों के निर्माण से डॉ. कलाम के मजबूत भारत के सपने को ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई रक्षा कंपनियां भारत की आजादी के इस अमृत काल के दौरान देश के लिए एक नए भविष्य के सृजन से जुड़े विभिन्न संकल्पों का हिस्सा हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इन कंपनियों को बनाने का निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये 7 नई कंपनियां आने वाले समय में देश की सैन्य ताकत के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करेंगी। भारतीय आयुध कारखानों के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद की अवधि में इन कंपनियों के उन्नयन की अनदेखी की गई, जिससे देश अपनी जरूरतों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हो गया। उन्होंने कहा कि ये 7 रक्षा कंपनियां इस स्थिति को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

श्री मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि ये नई कंपनियां 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप आयात प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को 65,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर प्लेस किए हैं जो इन कंपनियों में देश के विश्वास को दिखाता है।

श्री मोदी ने कहा कि आज निजी और सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के मिशन में साथ-साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने नए दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा गलियारों का हवाला दिया। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं और एमएसएमई के लिए नए अवसर उभर रहे हैं और इस तरह देश हाल के वर्षों में नीतिगत बदलावों का परिणाम देख रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 325 प्रतिशत बढ़ा है।

> यह हमारा लक्ष्य है कि हमारी कंपनियां न केवल अपने उत्पादों में विशेषज्ञता स्थापित करें, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड भी बनें। जहां प्रतिस्पर्धी लागत हमारी ताकत है, वहीं गुणवत्ता और विश्वसनीयता हमारी पहचान होनी चाहिए

श्री मोदी ने बताया कि यह हमारा लक्ष्य है कि हमारी कंपनियां न केवल अपने उत्पादों में विशेषज्ञता स्थापित करें, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड भी बनें। उन्होंने आग्रह किया कि जहां प्रतिस्पर्धी लागत हमारी ताकत है, वहीं गुणवत्ता और विश्वसनीयता हमारी पहचान होनी चाहिए। श्री मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र या किसी कंपनी का विकास और ब्रांड मूल्य उसके अनुसंधान एवं विकास और नवाचार से निर्धारित होता है। उन्होंने नई कंपनियों से अपील की कि अनुसंधान और नवाचार उनकी कार्य-संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, ताकि वे भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अगुवाई करें।

श्री मोदी ने कहा कि यह पुनर्गठन नई कंपनियों को नवाचार और विशेषज्ञता का विकसित करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा और नई कंपनियों को ऐसी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने स्टार्ट-अप्स से इन कंपनियों के माध्यम से एक दूसरे के अनुसंधान और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए इस नई यात्रा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। ■

फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

गत 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 (1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के लिए अनुमोदित दरें निम्नानुसार होंगीः

प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर (रुपये में)	
एन (नाइट्रोजन)	18.789
पी (फास्फोरस)	45.323
के (पोटाश)	10.116
एस (सल्फर)	2.374

(1) रोलओवर की कुल राशि 28,602 करोड़ रुपये होगी।

(2) 5,716 करोड़ रुपये की संभावित अतिरिक्त लागत पर डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज।

(3) 837 करोड़ रुपये की अस्थायी लागत पर तीन सबसे अधिक खपत वाले एनपीके ग्रेड अर्थात एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 और एनपीके 12-32-16 पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज। कुल आवश्यक सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपये होगी।

साथ ही, सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत गुड़ (0:0:14.5:0) से प्राप्त पोटाश को शामिल करने को भी मंजूरी दी।

दरअसल, बचत घटाकर रबी 2021-22 के लिए आवश्यक निवल सब्सिडी 28,655 करोड़ रुपये होगी।

लाभ

यह रबी सीजन 2021-22 के दौरान उर्वरकों की रियायती/सस्ती कीमतों पर किसानों को सभी पीएंडके उर्वरकों की सुगम उपलब्धता को सक्षम करेगा और वर्तमान सब्सिडी स्तरों को जारी रखते हुए और डीएपी तथा सर्वाधिक खपत वाले तीन एनपीके ग्रेड के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के विशेष पैकेज देकर कृषि क्षेत्र का समर्थन करेगा।

यह डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर 438 रुपये प्रति बैग और एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 और एनपीके 12-32-16 पर 100 रुपये प्रति बैग का लाभ देगा, ताकि किसानों के लिए इन उर्वरकों की कीमतें सस्ती बनी रहें। ■

ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक हुए पंजीकृत

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार दो महीने से भी कम समय में 4 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट संदेश में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजीकरण कराने से असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सकेगा।

निर्माण, परिधान निर्माण, मछली पकड़ने, गिग और प्लेटफॉर्म वर्क, स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू कार्य, कृषि और संबद्ध कार्यों, परिवहन क्षेत्र जैसे विविध व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या भी जुड़ी हुई है। प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पोर्टल पर 4.09 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 50.02 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं और 49.98 प्रतिशत पुरुष हैं। यह उत्साहजनक है कि पुरुषों और महिलाओं का समान अनुपात इस अभियान का हिस्सा रहा है।

भारत में रोजगार सृजन में इन दो क्षेत्रों की विशाल मात्रा को देखते हुए पंजीकृत श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या कृषि और निर्माण से है। इसके अतिरिक्त घरेलू और गृह कार्य से जुड़े श्रमिकों, परिधान क्षेत्र के श्रमिकों, ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्ड वेयर श्रमिकों, पूंजीगत वस्तु श्रमिकों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य, खाद्य उद्योग तथा अन्य कई जैसे– विविध और विभिन्न व्यवसायों के श्रमिकों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

इन पंजीकृत श्रमिकों में से लगभग 65.68 प्रतिशत 16-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 34.32 प्रतिशत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के हैं। इन श्रमिकों की सामाजिक संरचना में इन श्रेणियों से क्रमशः लगभग 43 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सामान्य जातियां शामिल हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 23 प्रतिशत और 7 प्रतिशत श्रमिक शामिल हैं। ■

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन- अमृत 2.0 को मिली मंजूरी

अमृत 2.0 सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को 2025-26 तक नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत 2.0) को 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए शहरों को 'जल सुरक्षित' एवं 'आत्मनिर्भर' बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दे दी। दरअसल, शहरी परिवारों को विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह सभी घरों को चालू नल कनेक्शन प्रदान करके, जल स्रोत संरक्षण/वृद्धि, जल निकायों और कुंओं का कायाकल्प, शोधित किए गए पानी का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इस परियोजना से शहरी परिवारों को पाइप से जलापूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज की सुविधा उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सुगमता लायी जाएगी।

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए 'अटल मिशन' देश का पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है जिसे जून, 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था। अब तक 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर/सेप्टेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 6,000 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें से 1,210 एमएलडी क्षमता पहले से ही बनाई जा चुकी है, जिसमें 907 एमएलडी शोधित सीवेज के पुनः उपयोग का प्रावधान है। 3,600 एकड़ क्षेत्रफल वाले 1,820 उद्यान विकसित किए गए हैं, जबकि अन्य 1,800 एकड़ क्षेत्र में हरियाली है। अब तक 1,700 बाढ़ बिंदुओं को समाप्त कर दिया गया है।

अमृत के तहत किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अमृत 2.0 सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखता है। 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज इसका एक और उद्देश्य है। मिशन का लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करना है।

अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की सम्बद्धता को अनुमोदन

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्तूबर को सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के साथ सम्बद्ध होने वाले विद्यालयों को लॉन्च करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे, जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे। प्रथम चरण में 100 सम्बद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों/एनजीओ/निजी भागीदारों से लिया जाना प्रस्तावित है।

दरअसल, देशभर में फैले 33 सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने के लिए आवेदन हेतु सरकारी/निजी स्कूलों/एनजीओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

इस योजना से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी सहभागिता को बल मिलेगा, जिससे प्रतिष्ठित निजी और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और सैनिक स्कूल परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई क्षमताओं का विकास होगा।

अकादमिक वर्ष 2022-23 की शुरुआत से तकरीबन 5,000 छात्रों के कक्षा-VI में ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में प्रवेश लेने की उम्मीद है। वर्तमान में मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा-VI में तकरीबन 3,000 छात्रों के प्रवेश की क्षमता है।

उल्लेखनीय है कि पाठ्यक्रम सहित नियमित बोर्ड के साथ सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के एकीकरण से अकादमिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से तंदरूस्त, सांस्कृतिक रूप से जागरूक, बौद्धिक रूप से निपुण, कौशल संपन्न युवा और योग्य नागरिकों को तैयार किया जा सकता है। ■

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

(गतांक से...)

राज्य-आवश्यकता

कृत युग में जब मानव परस्पर धर्म के आधार पर एक-दूसरे की रक्षा करते थे, राज्य नहीं था। किंतु वह एक आदर्श स्थिति है और तभी संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः द्वंद्वातीत, निस्स्वार्थ, निस्पृही एवं धर्मनिष्ठ हो। सामान्यतः समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने तथा प्रत्येक घटक को धर्मपालन को सुविधा देने के लिए राज्य एक आवश्यक संस्था है।

आदर्श राज्य-धर्मराज्य

भारतीय राज्य का आदर्श 'धर्मराज्य' रहा है। यह एक असांप्रदायिक राज्य है। सभी पंथों और उपासना पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता एवं समादर का भाव भारतीय राज्य का आवश्यक गुण है। अपनी श्रद्धा और अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक नागरिक का उपासना का अधिकार अक्षुण्ण हैं तथा राज्य के संचालन अथवा नीति निर्देशन में किसी भी व्यक्ति के साथ मत या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। धर्मराज्य थियोक्रेसी अथवा मजहबी राज्य नहीं है।

भारतीय राज्य का आदर्श 'धर्मराज्य' रहा है। यह एक असांप्रदायिक राज्य है। सभी पंथों और उपासना पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता एवं समादर का भाव भारतीय राज्य का आवश्यक गुण है

'धर्मराज्य' किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सर्वसत्तासंपन्न नहीं मानता। सभी नियमों और कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। कार्यपालिका, विधायिका और जनता सबके अधिकार धर्माधीन हैं। स्वैराचरण कहीं भी अनुमत नहीं। अंग्रेजी का 'Rule of Law' (विधि के अनुसार शासन) धर्मराज्य की कल्पना को व्यक्त करनेवाला निकटतम शब्द है। निरंकुश और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को रोकने तथा लोकतंत्र को स्वच्छंदता में विकृत होने से बचाने में धर्मराज्य ही समर्थ है। राज्यों की अन्य कल्पनाएं अधिकारमूलक हैं, किंतु धर्मराज्य कर्तव्य-प्रधान है। फलतः इसमें अपने अधिकारों के हनन की आशंका असीम अधिकार प्राप्ति की लालसा, सीमित अधिकारों से असंतोष, अधिकारारूढ होने पर कर्तव्यों की उपेक्षा अधिकारमद, विभिन्न अधिकारों के बीच संघर्ष इन सबके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

कर्तव्य और अधिकार

'धर्मराज्य' में जनाधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जनता का इन मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक रहना कर्तव्य है। बिना इसके धर्मपालन संभव नहीं। 'अधिकार' वह उपादान है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तथा एक बड़ी सत्ता के अंगभूत होने की अनुभूति करता है। कर्तव्य और अधिकार उस त्रिकोण की दो भुजाएं हैं, धर्म जिसका आधार है। सैनिक का अधिकार है कि उसे शस्त्र मिले, बिना उसके वह रक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। शस्त्र की उपलब्धि और प्रयोग कब और कैसे हो, इसका नियमन धर्म से होता है।

लोकतंत्र

लोकाधिकार की प्रतिष्ठा और लोक-कर्तव्य के निर्वाह का लोकतंत्र एक साधन है। केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी लोकतंत्र चाहिए। वास्तव में जनतंत्र अविभाज्य है। किसी भी एक क्षेत्र में लोकतंत्र का अभाव एक-दूसरे क्षेत्र में लोकतंत्र को नहीं पनपने देगा। सहिष्णुता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा समष्टि के साथ एकात्मकता लोकतंत्र के प्राण हैं। बिना इन भावों के लोकतंत्र का बाहरी स्वरूप निष्प्राण एवं जड़ है। यदि चैतन्य विद्यमान है तो देश-काल-परिस्थिति से लोकतंत्र के रूप में भेद हो सकता है।

अपने प्रतिनिधि चुनने और चुने जाने का अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए व्यवसाय और उपभोग की स्वतंत्रता आवश्यक है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता से सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इस बात का प्रयत्न करना होगा कि ये अधिकार एक-दूसरे के पूरक एवं पोषक रहें, विरोधी एवं विनाशक नहीं।

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता मानव और राष्ट्र की स्वाभाविक आकांक्षा है। पराधीनता में न तो सुख है, न शांति। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक और

सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए। शासन का व्यष्टि और समष्टि के प्राकृतिक हित में हस्तक्षेप न करना तथा सदैव उसके अनुकूल चलना राजनीतिक स्वतंत्रता है। अर्थ के होने अथवा उसके न होने से मनुष्य के हित में विघ्न न होना ही आर्थिक स्वतंत्रता है। समाज का व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में बाधक न होकर साधक होना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं के राष्ट्रगत हुए बिना ये व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकतीं। राज्य के सब अंगों द्वारा अपने-अपने कर्तव्य का पालन करने से सबको स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

लोकतंत्र के समान स्वतंत्रता भी अविभाज्य है। बिना शासनिक स्वतंत्रता के अन्य दो स्वतंत्रताएं नहीं हो सकतीं। बिना आर्थिक स्वतंत्रता के मनुष्य को सामाजिक और कुछ अंशों में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती तथा बिना सामाजिक स्वतंत्रता के अर्थ मनुष्य को भाव और अभाव दोनों रूपों में परतंत्र कर देता है।

अर्थायाम

शासन तंत्र के समान अर्थ-तंत्र में भी अराजकता केवल कृत युग की चीज़ है, अर्थात् अहस्तक्षेप (Laissez faire) का सिद्धांत इसी अवस्था में सर्वहितकारी रूप से चल सकता है, अन्यथा नहीं। अतः अर्थ के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग को व्यवस्थित करने के लिए अर्थायाम आवश्यक है। इस हेतु अर्थ के क्षेत्र में भी अनेक संस्थाओं का जन्म होता है। राज्य का भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण दायित्व है। किंतु सभी उद्योगों अथवा उत्पादन के साधनों का राज्य के स्वामित्व तथा प्रबंध के अधीन होना आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को जन्म देता है। अतः यह ठीक नहीं। पर यह भी स्वीकार करना होगा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के आरंभ के लिए अर्थव्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र के आधारभूत लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक क्षेत्र में नियोजन, निर्देशन, नियमन, नियंत्रण का सामान्यतः तथा विशेष क्षेत्रों और स्थितियों में स्वामित्व और प्रबंध का भी दायित्व ले।

अर्थ का अभाव और प्रभाव

अर्थ के अभाव से तो धर्म का ह्रास होता ही है, अर्थ का प्रभाव भी धर्म की हानि करता है। अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों से आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है। सुसाध्य आजीविका की अप्राप्ति तथा उत्पादन को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी अर्थ का अभाव है। यह बात व्यक्ति और राष्ट्र दोनों पर लागू होती है। अर्थ की साधनता को भुलाकर उसमें आसक्ति, अर्थ से धर्मानुकूल कामोपभोग की इच्छा का, ज्ञान का और शक्ति का अभाव, अर्थ का अनुचित घमंड, समाज में आर्थिक विषमता, मुद्रा का आधिक्य एवं अवमूल्यन, वे कारण हैं, जिनसे अर्थ का प्रभाव मानव की कर्मशक्ति को कुंठित कर अर्थ और श्री के ह्रास का कारण बनता है।

अर्थ के अभाव से तो धर्म का ह्रास होता ही है, अर्थ का प्रभाव भी धर्म की हानि करता है। अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों से आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है। सुसाध्य आजीविका की अप्राप्ति तथा उत्पादन को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी अर्थ का अभाव है। यह बात व्यक्ति और राष्ट्र दोनों पर लागू होती है

संपत्ति का स्वामित्व

संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। कुछ लोग संपत्ति पर व्यक्ति का निर्बाध अधिकार मानते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं, जो निजी संपत्ति को, विशेषकर उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को, सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। 'ईशावास्यमिदं सर्वं' के आधार पर कुछ तत्त्व संपूर्ण संपत्ति को ईश्वर की मानकर मनुष्य को विश्वस्त के नाते उसका उपयोग करने का परामर्श देते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 'विश्वस्त' का विचार अच्छा है, किंतु व्यवहार में 'विश्वस्त' को न्याय के किन नियमों और निर्देशों से बांधा जाए और कौन बांधे, यह प्रश्न तो बना ही रहता है।

व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह, जिसके साथ व्यक्ति जीवन के सभी प्रमुख व्यवहारों तथा आवश्यकताओं के लिए निगडित है, बिना संपत्ति के नहीं रह सकता। कर्म के साथ कर्मफल जुड़ा अर्जित के उपभोग एवं उपयोग की स्वतंत्रता में से संपत्ति पैदा होती है। संपूर्ण आय का उपभोग न कर बचत करना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय गुण है। संपत्ति में भी मानव को प्रतिष्ठा, सुरक्षा तथा तुष्टि की अनुभूति होती है। अतः हम संपत्ति को पूरी तरह नहीं मिटा सकते।

संपत्ति का आधार समाज-सापेक्ष है। सब वस्तुओं के लिए एक सी संपत्ति व्यवस्था नहीं है। एक ही वस्तु के लिए सब स्थानों पर और सब समय के लिए एक व्यवस्था नहीं है। यह विभेद समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित हुआ है। जो लोग समाज को संपत्ति का नियंता नहीं मानते, वे केवल इतना चाहते हैं कि समाज विद्यमान मान्यताओं में परिवर्तन न करे। समाज को इस बात का अधिकार है तथा अनेक बार उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह संपत्ति संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन करे। संपत्ति का अबाध एवं अपरिवर्तनीय अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है।

संपत्ति का अधिकार हमें मर्यादाओं के अंतर्गत स्वीकार करना होगा। इन सीमाओं का निर्धारण समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं जीवन-मूल्यों के आधार पर निश्चित होना चाहिए। जब संपत्ति अपने प्रभाव से स्वामी को आलसी या विलासी और दूसरों को अभावग्रस्त या परतंत्र बनाए तो उसका नियमन आवश्यक है।

संपत्ति संबंधी अधिकारों में परिवर्तन होने पर प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास का दायित्व मूलतः समाज पर आता है। किंतु क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नैश्चिंत्य तथा स्थायित्व की दृष्टि से आवश्यक है। ■

(क्रमशः...)

अजातशत्रु कैलाशपति मिश्र

(5 अक्टूबर, 1923 – 3 नवंबर, 2012)

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री कैलाशपति मिश्र को बिहार भाजपा का 'भीष्म पितामह' कहा जाता है। श्री मिश्र का जन्म बक्सर जिले में दुधारचक गांव में 5 अक्तूबर, 1923 को हुआ था। पंडित हजारी मिश्र के अत्यंत साधारण व अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेने के बावजूद बाल्यकाल से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी हो गए। 1942 के 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में 10वीं के छात्र रहते हुए जेल गए। 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, तो फिर अपने राष्ट्र और समाज की सेवा ही उनका ध्येय बन गया। आजीवन अविवाहित रहकर अपने समाज की सेवा का जो संकल्प उन्होंने 1945 में लिया, उसे अंत तक निभाया।

श्री मिश्र ने संघ प्रचारक के रूप में आरा से सामाजिक जीवन प्रारंभ किया। वे 1947 से 52 तक पटना में प्रचारक रहे, 1952 से 57 तक पूर्णिया के जिला प्रचारक रहे, फिर संघ के निर्देश पर ही जनसंघ में गए। 1959 में उन्हें जनसंघ के प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व मिला, तो उन्होंने आपातकाल के बाद चुनावी राजनीति में उतरने के निर्देश का भी पालन किया। श्री मिश्र ने विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते तथा कर्पूरी ठाकुर की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे।

श्री मिश्र 1980 में जनसंघ के नए रूप में सामने आयी भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए, फिर 1983 से 1987 तक निर्वाचित अध्यक्ष रहे। इस बीच वे 1984 से 1990 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही उन्होंने अनेक राज्यों के संगठन मंत्री का दायित्व भी बखूबी निभाया। 7 मई, 2003 से 7 जुलाई, 2004 तक वे गुजरात के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। इसी दौरान 4 माह के लिए राजस्थान के राज्यपाल का कार्यभार भी उन पर था। श्री मिश्र सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती राजनीतिक यात्रा में भी कभी नहीं डिगे, कभी विचलित नहीं हुए।

50 वर्ष से अधिक लम्बी चली उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा में उन पर न कोई आरोप लगा और न ही वे किसी विवाद का अंग बने। राजनीति की दलदल में कमल के समान अहंकार, बुराई, द्वेष, लोभ-लालच आदि सामान्य दोषों से भी अछूते रहने वाले श्री कैलाशपति मिश्र अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए आज भी आदर्श एवं प्रेरणास्रोत हैं।

श्री मिश्र एक साहित्यकार भी थे। इनकी लिखी पुस्तकों में 'पथ के संस्मरण' (आत्मकथा) और 'चेतना के स्वर' (कविता संग्रह) प्रमुख हैं। इनका देहावसान 3 नवंबर, 2012 को पटना में हुआ। ■

राजनैतिक जीवन

- 1942 के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी (10वीं का छात्र रहते जेल गए)
- 1945: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े (संघ परिवार को समर्पित किया जीवन, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प)
- 1945-46: आरा के प्रचारक
- 1959: प्रदेश संगठन मंत्री
- 1977-80: विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक
- 1980: बिहार भाजपा के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष
- 1983-87: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
- 1984-90: राज्यसभा सदस्य
- 1988-93: भाजपा राष्ट्रीय मंत्री
- 1993-95: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
- 1995-2003: भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
- राष्ट्रीय मंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व अंडमान निकोबार के संगठन मंत्री
- 7 मई, 2003 – 7 जुलाई, 2004: गुजरात के राज्यपाल (इसी दौरान चार महीने के लिए राजस्थान के भी राज्यपाल)

रक्षा निर्माण को मिली नई उड़ान

राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री, भारत सरकार

किसी भी बड़े सुधार की शुरुआत करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए धैर्य, प्रतिबद्धता तथा संकल्प की आवश्यकता होती है। हितधारकों की प्रतिस्पर्धी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यथास्थिति में बदलाव के लिए सूक्ष्म संतुलित प्रयास आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार ऐसे मजबूत निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सुधार करने में कभी नहीं हिचकिचाती, जो लाभदायक होने के साथ-साथ राष्ट्र के दीर्घकालिक हित में हों।

रक्षा में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। सरकार द्वारा हाल में 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति को और गति मिली है। भारतीय रक्षा उद्योग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को भी विकसित किया है। निर्यात में हाल की सफलताओं से प्रेरित होकर भारत एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निर्यात सहित बाजार तक पहुंच के साथ-साथ डिजाइन से लेकर उत्पादन तक भारत को रक्षा क्षेत्र के मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित करना है।

वर्ष 2014 के बाद से भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, ताकि निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्वदेशी उत्पादों की मांग को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनुकूल तंत्र तैयार किया जा सके। आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के अधीन था, जिसे शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली सात नई कारपोरेट संस्थाओं में बदलने का

रक्षा में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। सरकार द्वारा हाल में 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति को और गति मिली है। भारतीय रक्षा उद्योग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को भी विकसित किया है

ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ताकि कार्य स्वायत्तता व दक्षता को बढ़ाया जा सके और नई विकास क्षमता तथा नवाचार को शुरू किया जा सके। इस निर्णय को निःसंदेह इस शृंखला का सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। आयुध निर्माण संयंत्रों का 200 से भी अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उनका बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक संपदा हैं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में सशस्त्र बलों द्वारा ओएफबी उत्पादों की उच्च लागत, असंगत गुणवत्ता और आपूर्ति में देरी से संबंधित चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की मौजूदा प्रणाली में कई खामियां थीं। सात नई कारपोरेट इकाइयां बनाने का यह निर्णय व्यापार प्रशासन के मॉडल में उभरने के लक्ष्य के अनुरूप है। यह नई संरचना इन कंपनियों के प्रतिस्पर्धी बनने और आयुध कारखानों को अधिकतम उपयोग के माध्यम से उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों के रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्पादों की विविधता के मामले में विशेषज्ञता को गहराई प्रदान करेगी। गुणवत्ता एवं लागत संबंधी दक्षता में सुधार करते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगी और नवाचार एवं लक्षित सोच (डिजाइन थिंकिंग) के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी। सरकार ने इसके साथ ही यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)

मुख्य रूप से विभिन्न क्षमता वाले गोला-बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन से जुड़ी होगी। बख्तरबंद वाहन कंपनी (अवनी) मुख्य रूप से टैंक और बारूदी सुरंग रोधी वाहन (माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल) जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के उत्पादन में संलग्न होगी और इसके द्वारा अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करते हुए घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद है। यही नहीं, यह नए निर्यात बाजारों में भी पैठ बना सकती है। उन्नत हथियार एवं उपकरण (एडब्ल्यूई इंडिया) मुख्य रूप से तोपों और अन्य हथियार प्रणालियों के उत्पादन में संलग्न होगी। इसके द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद है। अन्य चार कंपनियों के साथ भी यही स्थिति रहेगी।

ओएफबी के सभी लंबित वर्क आर्डर, जिनका मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक है, को अनुबंधों के जरिये इन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा, विविधीकरण और निर्यात के माध्यम से कई क्षेत्रों में नई कंपनियों के फलने-फूलने की काफी संभावनाएं हैं। असैन्य इस्तेमाल के लिए दोहरे उपयोग वाले रक्षा उत्पाद भी इनमें शामिल हैं। इसी तरह आयात प्रतिस्थापन के जरिये भी नई कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा।

वैसे तो आयुध कारखानों को पहले सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नई कंपनियां उस दायरे से भी परे जाकर देश-विदेश में नए अवसरों का पता लगाएंगी। पहले के मुकाबले कहीं अधिक कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता मिल जाने से ये नई कंपनियां अब आधुनिक कारोबारी माडलों को अपना सकेंगी।

अभी हम आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर सुव्यवस्थित ढंग से विशेष जोर देने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह परिकल्पना की गई है कि इन नई कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा कंपनियां देश में एक मजबूत 'सैन्य औद्योगिक परिवेश' बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेंगी। इससे हमें समय पर स्वदेशी क्षमता विकास की योजना बनाकर आयात को कम करने और इन संसाधनों को स्वदेश में ही बने रक्षा उत्पादों की खरीद में लगाने में काफी मदद मिलेगी। इसमें सफलता मिलने पर हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हालांकि, इसमें कई चुनौतियां हैं।

यह सही है कि सदियों पुरानी परंपराओं और कार्य-संस्कृति को रातोंरात बदलना मुश्किल है। फिर भी हमारा मंत्रालय शुरुआती मुद्दों को हल करने एवं मार्गदर्शन करने के साथ-साथ इन नवगठित कंपनियों को व्यवहार्य या लाभप्रद व्यावसायिक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगा। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहयोग प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नए सिरे से शुरू हो रहे सहयोग प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज से पुनः शुरू हुआ भाजपा का केंद्रीय सहयोग प्रकोष्ठ आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित निदान का एक सशक्त मंच बनेगा। आज प्रथम दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल की है।

सहयोग प्रकोष्ठ हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से चलेगा। प्रतिदिन कोई न कोई केंद्रीय मंत्री आम जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और उसके समाधान के लिए उचित कदम निर्देशित करेंगे।

ज्ञात हो कि 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सहयोग प्रकोष्ठ में कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनने और निवारण के लिए सहयोग प्रकोष्ठ की भूमिका बढ़ी थी और तब पार्टी और सरकार की ओर से समेकित रूप से व्यवस्था शुरू हुई थी। कोरोना काल में यह व्यवस्था बाधित हुई जिसे पुनः 11 अक्टूबर, 2021 से प्रारंभ किया गया है। ■

'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के साथ अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है: नरेन्द्र मोदी

भारत के लोग, भारतीय उद्योग, भारतीय व्यवसाय, भारतीय विनिर्माता, भारतीय किसान गतिशक्ति के महाभियान के केंद्र में हैं तथा 'गतिशक्ति योजना' समग्र शासन का विस्तार है

गत 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए 'पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान' का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री आर.के. सिंह, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यों के मंत्री, प्रतिष्ठित उद्योगपति उपस्थित थे। उद्योग जगत से आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिड़ला; ट्रैक्टर्स एंड फर्म इक्विपमेंट की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन; टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक श्री टी.वी. नरेंद्रन और रिविगो के सह संस्थापक श्री दीपक गर्ग ने अपने विचार व्यक्त किए।

श्री मोदी ने इस अवसर पर अष्टमी के शुभ दिन यानी 'शक्ति की पूजा' के दिन का उल्लेख किया और कहा कि इस शुभ अवसर पर देश की प्रगति की रफ्तार को भी नई शक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के साथ आज अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के विश्वास को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तक ले जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति (गतिशक्ति) देगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गतिशक्ति के इस महाभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान हैं। यह भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा।

श्री मोदी ने कहा कि इन तमाम वर्षों में 'कार्य प्रगति पर है' का बोर्ड विश्वास की कमी का प्रतीक बन गया था और प्रगति के लिए रफ्तार, उत्सुकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आज का 21वीं सदी का भारत पुरानी प्रणालियों और तौर-तरीकों को पीछे छोड़ रहा है।

आज का मंत्र है–

"प्रगति के लिए कार्य,
प्रगति के लिए संपत्ति,
प्रगति के लिए योजना,
प्रगति के लिए प्राथमिकता।"

उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने का 'वर्क-कल्चर' विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्टस पूरे करने का प्रयास हो रहा है। श्री मोदी ने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा-पत्र में भी नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल, देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने लगे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है, जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है।

उन्होंने कहा कि मैक्रो प्लानिंग और सूक्ष्म कार्यान्वयन के बीच व्यापक अंतर के कारण समन्वय की कमी, अग्रिम जानकारी की कमी, बंद परिवेश में सोचने और काम करने से निर्माण में बाधा आ रही है और बजट की बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि शक्ति बढ़ने या वृद्धि होने के बजाय विभाजित हो जाती है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसका समाधान करेगा, क्योंकि मास्टर प्लान के आधार पर काम करने से संसाधनों का मनोवांछित उपयोग होगा।

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान न केवल सरकारी प्रक्रिया और इसके विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है, बल्कि परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने में भी मदद करता है। यह समग्र शासन का एक विस्तार है

श्री मोदी ने 2014 को याद किया जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब उन्होंने सैकड़ों अटकी परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी परियोजनाओं को एकल प्लेटफॉर्म पर रखा और बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि अब समन्वय की कमी के कारण देरी से बचने पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार की सामूहिक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब दशकों से अधूरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान न केवल सरकारी प्रक्रिया और इसके विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है, बल्कि परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि यह समग्र शासन का एक विस्तार है।

श्री मोदी ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत में पहली इंटरस्टेट नैचुरल गैस पाइपलाइन साल 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद साल 2014 तक यानी 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नैचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देशभर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 5-6 वर्षों में पूरा होने का लक्ष्य है।

बीते 7 वर्षों में 9,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग

श्री मोदी ने कहा कि 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 9,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था, जबकि बीते 7 सालों में हमने 24 हजार किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया है।

श्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो रेल महज 250 किलोमीटर के ट्रैक पर चल रही थी। आज मेट्रो का विस्तार 700 किलोमीटर तक कर दिया गया है और 1000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। 2014 से पहले के पांच वर्षों में केवल 60 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। पिछले 7 वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क्स थे। आज देश में 19 मेगा फूड पार्क्स काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2014 में सिर्फ 5 जलमार्ग थे, आज भारत में 13 कार्यशील जलमार्ग हैं। बंदरगाहों पर जहाजों का टर्न-अराउंड समय 2014 के 41 घंटे से घटकर 27 घंटे हो गया है। उन्होंने कहा कि देश ने 'वन नेशन वन ग्रिड' के संकल्प को साकार किया है। 2014 के 3 लाख सर्किट किलोमीटर बिजली पारेषण लाइनों की तुलना में आज भारत में 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर लाइनें हैं।

श्री मोदी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत विश्व का व्यापारिक केन्द्र बनने के सपने को साकार कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य असाधारण हैं और इसके लिए असाधारण प्रयासों की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों को साकार करने में 'पीएम गतिशक्ति' सबसे ज्यादा मददगार होगी। जिस तरह जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी ने लोगों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच में क्रांति ला दी, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए 'पीएम गतिशक्ति' भी ऐसा ही करेगी। ■

'कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा के प्रति पुष्पांजलि है'

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट से पहले ही आठ एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में एयरपोर्ट परियोजनाएं चल रही हैं

गत 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। सभा में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्वभर के बौद्ध समाज के लिए भारत श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह सुविधा उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक की संपूर्ण यात्रा का साक्षी यह क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है।

श्री मोदी ने यह रेखांकित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कुशीनगर में उतरने वाली श्रीलंका की फ्लाइट और वहां के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश 'सबका साथ और सबका प्रयास' की सहायता से सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का विकास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है।

श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन का चाहे जो स्वरूप हो, चाहे वह आस्था के लिये या आराम के लिये; उसके लिये रेल, सड़क, हवाई मार्ग, जलमार्ग, होटल, अस्पताल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सीवर उपचार और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा से युक्त सभी आधुनिक अवसंरचना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये सब आपस में जुड़े हैं और इन सब पर एक साथ काम करना अहम है। आज का 21वीं सदी का भारत इसी पथ पर आगे बढ़ रहा है।

श्री मोदी ने घोषणा की कि उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है, इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। पचास से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे, उनको चालू किया जा चुका है।

> भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश 'सबका साथ और सबका प्रयास' की सहायता से सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विमानन सेक्टर के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी (वायु संपर्कता) में लगातार सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट से पहले ही आठ एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में एयरपोर्ट परियोजनाएं चल रही हैं।

एयर इंडिया पर हाल में लिये गये फैसले का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयरस्पेस को सिविल यूज़ के लिए खोलने से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हाल में लॉन्च ड्रोन नीति से कृषि से स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन से रक्षा तक के क्षेत्रों में जीवनोपयोगी बदलाव आयेगा।

श्री मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री गति शक्ति–राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में कहा कि इससे गवर्नेंस में तो सुधार आएगा ही, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज़ हो, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की क्षमता बढ़ाएं। ■

मानवाधिकारों की अवधारणा का गरीबों की गरिमा से गहरा संबंध है: नरेन्द्र मोदी

मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है

गत 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए मानवाधिकारों की प्रेरणा का, मानवाधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है।

प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमने अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध किया, हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को 'अधिकार और अहिंसा' का मार्ग सुझाया। हमारे बापू को देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है।

उन्होंने कहा कि बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं, जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। श्री मोदी ने कहा कि मानवाधिकार की अवधारणा का गरीबों की गरिमा से गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि जब गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का बराबर लाभ नहीं मिलता है तो अधिकारों का सवाल उठता है।

श्री मोदी ने गरीबों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उस गरीब को जब शौचालय मिलता है, तो उसे डिग्निटी भी मिलती है, इसी प्रकार जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था उस गरीब का जब जनधन खाता खुलता है, तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। इसी तरह, रुपे कार्ड, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन और पक्के मकानों का संपत्ति का अधिकार जैसे उपाय उस दिशा में प्रमुख कदम हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने ट्रांसजेंडर, बच्चों और घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया।

श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान गरीब, असहाय और वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाते में सीधे वित्तीय सहायता दी गई। 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' के लागू होने से प्रवासी मजदूरों की परेशानी काफी कम हुई। प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों की अपने-अपने तरीके से व्याख्या करने और देश की छवि खराब करने में मानवाधिकारों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध सचेत किया।

मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है। श्री मोदी ने सचेत करते हुए कहा कि इस तरह का सलेक्टिव व्यवहार, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है। श्री मोदी ने सचेत करते हुए कहा कि इस तरह का सलेक्टिव व्यवहार, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है।

उन्होंने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा है बल्कि यह हमारे कर्तव्यों का भी विषय है। यह कहते हुए कि 'अधिकार और कर्तव्य दो ऐसे रास्ते हैं जिन पर मानव विकास और मानव गरिमा की यात्रा आगे बढ़ती है', उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्य भी अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अलग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ■

आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है, उतनी पहले कभी नहीं रही: नरेन्द्र मोदी

हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए अतंरिक्ष क्षेत्र का मतलब सामान्य मानवी के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा से है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'इंडियन स्पेस एसोसिएशन' (आईएसपीए) का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज देश के दो महान सपूतों- 'भारत रत्न' जयप्रकाश नारायण और 'भारत रत्न' नानाजी देशमुख की जयंती का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों हस्तियों को नमन करते और श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आजादी के बाद के भारत को दिशा देने में इन दोनों महान व्यक्तित्वों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर, सबके प्रयास से राष्ट्र में कैसे बड़े-बड़े परिवर्तन आते हैं, इनका जीवन दर्शन हमें आज भी इसकी प्रेरणा देता है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है, उतनी पहले कभी नहीं रही। अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर आज भारत में जो बड़े सुधार हो रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है। उन्होंने इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) के गठन के लिए उपस्थित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

श्री मोदी ने कहा कि जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो हमारी अप्रोच चार पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की इनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवों की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना।

स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवों के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा! साथ ही, हमारे लिये स्पेस सेक्टर यानी इंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से डिलीवरी तक बेहतर स्पीड, हमारे मछुआरों के लिए स्पेस सेक्टर यानी बेहतर सुरक्षा के साथ-साथ आय तथा प्राकृतिक आपदा का बेहतर पूर्वानुमान का माध्यम है।

श्री मोदी ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान सिर्फ एक विजन

नहीं है बल्कि एक वेल-थॉट, वेल-प्लान्ड, इंटिग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर, भारत को ग्लोबल पॉवर हाउस बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के टेक्नोलॉजीकल एक्सपर्टीज को आधार बनाकर भारत को इनोवेशन्स का ग्लोबर सेंटर बनाए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, जो ग्लोबल डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगी, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेस और टेलेंट की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को लेकर सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है और जहां सरकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेट इंटरप्राइजेज के लिए ओपन कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने और त्रुटि-रहित, पारदर्शी शासन के एक उपकरण के रूप में परिवर्तित किया गया है। उन्होंने गरीबों के लिए आवास इकाइयों, सड़कों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जियो-टैगिंग के उपयोग का उदाहरण दिया। विकास परियोजनाओं की

निगरानी सैटेलाइट इमेजिंग द्वारा की जा रही है।

श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग 'फसल बीमा योजना' के दावों को निपटारे में हो रहा है, 'नाविक' प्रणाली मछुआरों की मदद कर रही है, इस तकनीक के माध्यम से आपदा प्रबंधन योजना भी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया। डिजिटल तकनीक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज शीर्ष डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से है, क्योंकि हम डेटा की शक्ति को सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं।

युवा उद्यमियों और स्टार्टअप के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर स्तर पर उद्योग, युवा इनोवेटर और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि एक मजबूत स्टार्टअप प्रणाली विकसित करने के लिए एक मंच का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्लेटफॉर्म सिस्टम को एक विजन के रूप में परिभाषित किया, जहां सरकार ओपन-एक्सेस सार्वजनिक नियंत्रित प्लेटफॉर्म बनाती है और इसे उद्योग और उद्यमों के लिए उपलब्ध कराती है। उद्यमी इस बुनियादी प्लेटफॉर्म पर नए समाधान तैयार करते हैं।

श्री मोदी ने इसे यूपीआई के प्लेटफॉर्म के उदाहरण के साथ स्पष्ट किया, जो एक मजबूत फिनटेक नेटवर्क का आधार बन गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्लेटफार्मों को स्पेस, भू-स्थानिक क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्री मोदी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आज उपस्थित लोगों के सुझावों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बहुत जल्द एक बेहतर स्पेसकॉम नीति और दूरसंवेदी (रिमोट सेंसिंग) नीति सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि 20वीं सदी में स्पेस और स्पेस पर राज करने की प्रवृत्ति ने दुनिया के देशों को किस तरह विभाजित किया। अब 21वीं सदी में स्पेस दुनिया को जोड़ने में, युनाइट करने में अहम भूमिका निभाए, ये भारत को सुनिश्चित करना होगा। ■

निर्मला सीतारमण ने जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में हुई आईएमएफ-विश्व बैंक की सालाना बैठकों से इतर इटली की अध्यक्षता में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की चौथी बैठक में भाग लिया।

यह इटली की अध्यक्षता में जी20 के अंतर्गत अंतिम एफएमसीबीजी बैठक थी और इसमें वैश्विक आर्थिक सुधार, कमजोर देशों को महामारी समर्थन, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु उपाय, अंतरराष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया व समझौते हुए।

महामारी से स्थायी रूप से उबरने के लिए जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर सहयोग उपायों को समय से पहले वापस लेने से बचने, साथ ही वित्तीय स्थायित्व और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखने व गिरावट के जोखिमों व नकारात्मकता प्रभाव बढ़ने से रोकने पर सहमत हो गए।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि संकट से सुधार की राह पर आने के लिए सभी को टीकों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि समर्थन जारी रखना, लचीलापन बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार और संरचनागत सुधार हमारे नीतिगत लक्ष्यों में शामिल होने चाहिए।

वित्त मंत्री ने ऋण राहत उपायों और नए एसडीआर आवंटन के माध्यम से महामारी पर प्रतिक्रिया और कमजोर देशों का समर्थन करने में जी20 की भूमिका की सराहना की। श्रीमती सीतारमण ने लक्षित देशों तक लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयास करने का सुझाव दिया।

वित्त मंत्री जी20 मंत्रियों और गवर्नरों के साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के प्रयासों को मजबूती देने की जरूरत पर सहमत हुईं। श्रीमती सीतारमण ने जोर देकर कहा कि विभिन्न देशों की अलग-अलग नीतियों और शुरुआती बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सफल परिणामों के लिए विचार-विमर्श को आगे ले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु न्याय की केंद्रीयता खासी अहम होगी।

अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से पैदा चुनौतियों के समाधान के लिए जी20 एफएमसीबीजी ने 8 अक्टूबर, 2021 को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) पर ओईसीडी/जी20 इनक्लूसिव फ्रेमवर्क द्वारा जारी दो सिद्धांतों वाले समाधान और विस्तृत कार्यान्वयन योजना में उल्लिखित समझौते को समर्थन दे दिया है। ■

आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करेगा
सहकार मंत्रालय

विकास आनन्द

भारत के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25 सितंबर को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा भी खड़ी करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता को समाजवाद और पूंजीवाद का विकल्प बताया है। 'अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन' (आईसीए) सहकारिता को 'संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ' के रूप में परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में, सहकारिता जीवन के हर क्षेत्र में सामूहिकता की भावना का संचार करती है; चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र हो। निश्चय ही यह आंदोलन सामाजिक पूंजी बनाने के साथ-साथ आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होगा। 'सामाजिक पूंजी' एक साझा मूल्य है जो व्यक्तियों को एक सामान्य उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए समूह में एक साथ काम करने की प्रेरणा देता है। एमाइल दर्खाइम, जॉर्ज सिमेल, वेबर जैसे कई विचारकों का मानना था कि औद्योगीकरण और शहरीकरण सामाजिक संबंधों को अचल रूप से बदल रहे हैं। उन्होंने मूल्यांकन किया कि औद्योगीकरण और शहरीकरण ने सामाजिक बंधन, सहयोग की समृद्ध परंपरा और नैतिक मूल्यों की क्षति पहुचाई है और मानव में अलगाव की भावना पैदा की है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि औद्योगीकरण और शहरीकरण विकासात्मक गतिविधि का एक हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में खामियां कहां हैं? खामियां हैं- उत्पादन के साधन के स्वामित्व को किस प्रकार नियमन करें? प्रमुख रूप से आर्थिक गतिविधियों के दो मॉडल दुनिया भर में प्रचलित हैं। पहला उत्पादन के साधनों पर 'निजी स्वामित्व' और दूसरा उत्पादन के साधनों पर 'राज्य का स्वामित्व'। निजी स्वामित्व ज्यादातर पूंजीवादी व्यवस्था में पाया जाता है और राज्य का स्वामित्व ज्यादातर समाजवादी व्यवस्था में पाया जाता है।

सहकारिता को इजरायल के विकास की रीढ़ माना जाता है। इजरायल की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तमाम बाधाओं के बावजूद आज इजराइल कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि प्रौद्योगिकी में दुनिया में अग्रणी है। किबुत्ज़ (सहकारिता) के तहत कृषि ने इज़राइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

उत्पादन का पूंजीवादी तरीका अपने मुनाफे को अधिकतम करने पर जोर देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत आय का असमान वितरण अमीर और गरीब की खाई को गहरा करता है। गरीब और गरीब होता जाता है व अमीर और अमीर होता जाता है। उत्पादन का यह तरीका कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को प्रोत्साहित करता है। कुछ लोगों के हाथ में धन के संचय के कारण आर्थिक लोकतंत्र के विचार को क्षति पहुंचती है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक असंतुलन होता है और उपभोक्ता की क्रयशक्ति कम हो जाती है। यह परिस्थिति राज्य को आर्थिक संकट की ओर ढकेलता है। समाजवादी व्यवस्था उद्यमशीलता के अवसरों को कम करती है और धीमी आर्थिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यह हर जगह विफल रही है। इस प्रणाली में एक बड़ी आबादी आर्थिक अवसरों से वंचित होता है। दूसरी ओर, यह लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ावा देती है और राज्य पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जाती है। दोनों ने समाज में साझा मूल्यों और सहयोग की भावना को प्रभावित किया है तथा आर्थिक लोकतंत्र के मूल्यों को भी बाधित किया है, जबकि 'आर्थिक लोकतंत्र' सहकारिता की मुख्य विशेषताओं में से एक है।

सहकार, यह साम्यवादी राज्य के विपरीत निजी संपत्ति के उन्मूलन पर नहीं, बल्कि कर्मचारी-नियोक्ता संबंध के परिवर्तन पर जोर देता है, उत्पादकों के स्वयं-प्रबंधन पर जोर देता है और यह स्थानीयता को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर दिया है। सहकारी आंदोलन के लिए अलग मंत्रालय बनाकर मोदी सरकार का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र को गहरा करने और हाशिए पर रहने वाले वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने का है। 30 सितंबर, 2018 को आणंद में अमूल के चॉकलेट प्लांट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में सहकारी आंदोलन ने समाजवाद और पूंजीवाद का एक सार्थक वैकल्पिक मॉडल प्रदान करता है। सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा लगभग एक सदी पहले सहकारिता के बोए गए बीज तीसरी वैकल्फिक आर्थिक व्यवस्था का उदाहरण बनकर तैयार

“ गुजरात में सहकारी आंदोलन ने समाजवाद और पूंजीवाद का एक सार्थक वैकल्पिक मॉडल दिया है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

“ सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा भी खड़ी करेगा।

अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

हुआ है, जहां न सरकार का कब्जा होगा, न धन्ना सेठों का कब्जा होगा; वो सहकारिता आंदोलन होगा और किसानों के, नागरिकों के, जनता-जनार्दन की सहकारिता से अर्थव्यवस्था बनेगी, पनपेगी, बढ़ेगी और हर कोई उसका हिस्सेदार होगा।

यह स्पष्ट है कि केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिया है कि सहकारिता ही समाजवाद और पूंजीवाद का विकल्प दे सकती है। सहकारी मॉडल में मौजूदा पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी दोनों के दोषों को कम करने की क्षमता है। सहकारी मॉडल सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत पर काम करती है। यह सही मायने में आर्थिक लोकतंत्र लाती है। बड़े कॉरपोरेट घरानों के विपरीत, जहां कॉरपोरेट मैनेजर और कॉरपोरेट शेयरधारकों द्वारा निर्णय लिया जाता है, सहकारिता में निर्णय लेने की शक्ति सदस्यों के समूह में होती है जिसमें निर्माता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और व्यापक जनता शामिल होती है और इसका लाभ सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। अमूल, लिज्जत पापड़, सरस, सुधा डेयरी सहकारिता आंदोलन के प्रतीक हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों रोजगार दिए हैं। लिज्जत पापड़ भारतीय महिला कामगारों का सहकार है जो विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में शामिल है और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है। अमूल और लिज्जत पापड़ अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में भी उभरे हैं। वे बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सहकारी प्रणाली विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के फलने-फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं।

ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं जहां सहकारिता ने उन्हें दुनिया में अग्रणी बना दिया। सहकारिता को इजरायल के विकास की रीढ़ माना जाता है। इजरायल की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तमाम बाधाओं के बावजूद आज इजराइल कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि प्रौद्योगिकी में दुनिया में अग्रणी है। किबुत्ज़ (सहकारिता) के तहत कृषि ने इज़राइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अनुसंधान और नवाचार ने देश की फसलों को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाने में शानदार तरीके से भूमिका निभाई है। सहकारी आंदोलन इस देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास में चमत्कार सिद्ध हुआ है। इज़राइल में सहकारी को किबुत्ज़ अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। 'किबुत्ज़' शब्द का अर्थ है इकट्ठा होना। युवा यहूदियों ने पहले कृषि और मानव निवास के उद्देश्य से दलदल और शुष्क भूमि पर बहुत मेहनत की थी, वे अपने लिए एक सामुदायिक संगठन बनाया। जमीन यहूदी राष्ट्रीय कोष बनाकर खरीदी गई। उन्होंने भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। इन अग्रदूतों ने कृषि पर स्थापित एक समूह का निर्माण किया, जिसे किबुत्ज़ के नाम से जाना जाता था। धीरे-धीरे इजराइल में कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए कई किबुत्ज़ अस्तित्व में आए। सहकारिता की भावना ने इज़राइल को कृषि में तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ाया और दुनिया में कृषि प्रौद्योगिकी में अग्रणी बन गया। 1960 के दशक में केवल 4% इज़राइली किब्बुत्ज़िम में रहते थे। वहीं, आज इज़राइल की संसद में किबुत्ज़निक सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत है।

दूसरा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के विकास का है। युद्ध के बाद के विकास के लिए जापान ने सहकारी दृष्टिकोण अपनाया। युद्ध पूर्व चार प्रमुख कंपनियां जिन्हें सामूहिक रूप से ज़ैबात्सु के नाम से जाना जाता था, का देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रभुत्व था। मित्र देशों की सेनाओं द्वारा जापान की हार के बाद ज़ैबात्सु को भंग कर दिया गया। युद्ध के बाद ज़ैबात्सुओं में शेयरधारिता पैटर्न को बदल दिया गया। परिवारों ने ज़ैबात्सु पर पूर्ण नियंत्रण खो दिया। युद्ध के बाद ज़ैबात्सु का स्वामित्व विभिन्न फर्मों, व्यक्तियों के पास आ गया, लेकिन एक परिवार के पास नहीं था। ज़ैबात्सुओं को पुनर्जीवित करने के इस सहकारी दृष्टिकोण ने जापान के तेज़ आर्थिक विकास में काफी मदद की है। युद्ध के बाद जापान में धन का संकेंद्रण बढ़ने के बजाय गिरा है। जापान के सहकारी दृष्टिकोण को 'सहकारी पूंजीवाद' भी कहा जाता है। इसने पूंजीवाद के बुराइयों को नहीं, गुणों को जरूर आत्मसात किया। नतीजतन, जापान में आय विषमता पश्चिमी विकसित देशों संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में बहुत कम है।

भारत में सहकारिता के लिए समर्पित मंत्रालय 'सहकार आंदोलन' की गति को तेज करेगा, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रह रहे वर्गों और कम विकसित क्षेत्रों के उत्थान का है। मोदी सरकार ने जून, 2021 में कृषि संबंधी सहकारी आंदोलन को सुव्यवस्थित करते हुए '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन' की योजना शुरू की है। 6,865 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 2027-28 तक 10,000 नए FPO बनाने और बढ़ावा देने का लक्ष्य है। अब तक सहकारी आंदोलन ने मुख्य रूप से बैंकिंग (क्रेडिट), कृषि, कृषि से संबंधित उत्पादों, आवास क्षेत्रों आदि पर ध्यान केंद्रित किया है। आने वाले दिनों में सहकारी दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों के लिए भी व्यवहार्य होगा। ■

(लेखक 'कमल संदेश' के एसोसिएट एडिटर हैं)

अफगान लोगों के मन में भारत के प्रति मित्रता की भावना है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान पर पहले जी20 विशेष शिखर सम्मेलन में 12 अक्टूबर को वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। ये बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी, जिसके पास वर्तमान में जी20 की अध्यक्षता है और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री श्री मारियो ड्रैगी ने की। इस बैठक में जिन मसलों पर विचार-विमर्श किया गया, वे अफगानिस्तान की मौजूदा मानवीय स्थिति, आतंकवाद संबंधी चिंताओं और वहां मानवाधिकारों के हाल से जुड़े थे।

अपनी टिप्पणी में श्री मोदी ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने हेतु बैठक बुलाने के लिए इटली जी20 प्रेज़िडेंसी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने लोगों के पारस्परिक संबंधों का जिक्र किया। श्री मोदी ने जिक्र किया कि बीते दो दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने याद किया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि अफगान लोगों के मन में भारत के प्रति मित्रता की भावना है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भूख और कुपोषण का सामना कर रहे अफगान लोगों का दर्द महसूस करता है।

श्री मोदी ने ये सुनिश्चित करने की जरूरत को भी रेखांकित किया कि क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर अफगान क्षेत्र कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत नहीं बन जाए। उन्होंने इस क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री मोदी ने अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन का आह्वान किया, जिसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक भी शामिल हों, ताकि बीते 20 सालों में हासिल की गई सामाजिक-आर्थिक तरक्की को बचाया जा सके और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपना समर्थन जताया और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 2593 में निहित संदेश के लिए जी20 के नए सिरे से समर्थन का आह्वान किया। ■

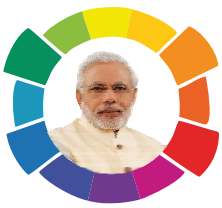

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

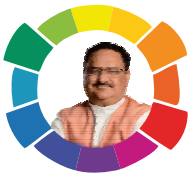

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

कोविड-19 रोधी टीकों की 100 करोड़ से अधिक खुराकें लगने के बाद नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र का दौरा के दौरान एक सुरक्षाकर्मी से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र पर एक दिव्यांग लाभार्थी से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान,
झज्जर स्थित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित
छात्रावास चरण-1 के भूमि पूजन समारोह में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं
शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं

दुश्मन के शस्त्र जो हो हज़ार
शत कोटि कवच से हम तैयार

मेरे भारत का ये विश्वास है
सबका साथ, सबका प्रयास है।

भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है...

#VaccineCentury

छायाकार: अजय कुमार सिंह